की एक्सपोर्ट न रुके, इस के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है और स्वेज केनाल के बन्द होने से एक्सपोर्ट की दृष्टि से हमारे देश पर कितना असर पड़ा है?

Dr. V. K. R. V. Rao: So far, we have no specific information as to how the exports have been affected Obviously the freight charges on exports have gone up, but whether it has any effect of either cancellation of contracts or reduction in the quantity exported, it is too early to say anything

Shri Tenneti Viswanatham: With reference to the hon Food Minister's answer that it is not the Egyptian Government that has stopped our ships, I would like to ask whether he is aware that Gen Nasser has said that as long as the Israeli troops are there, he is not going to release these ships; he has not advanced any mechanical difficulties

Shri Jagjiwan Ram: I have myself said that so long as the Israeli forces are on the banks of the Suez Canal it is not free from danger to pass any ship

पिता की सम्पत्ति में लड़की का हिस्सा

+

*1056 **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य विधान सभाओ ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि पिता की सम्पत्ति में लडकी को हिस्सा लेने की अनुमति न दी जाए,

(ख) क्या सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक सस्थाओ ने भी इसी आशय की मागें प्रस्तुत की है,

(ग) यदि हा, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में बने हुए कानून में निकट भविष्य में ही कुछ सशोधन करने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir

(c) and (d) In the open session of the 15th All India Akali Conference held at Karnal on 8th December, 1963 a resolution was passed (copy of which was forwarded to the Government by the Secretary, Shiromani Akali Dal, Amritsar) urging the Government to amend the Hindu Succession Act, 1956 in such a way as to provide a right of succession to the daughters-in-laws along with sons of the deceased intestate The ground given therein is this that the present provision in the Hindu Succession Act will result in the greatest fragmentation of agricultural property and create ill-will and family feuds between brothers and sisters

The President, All India Agriculturists Federation, New Delhi, All India Janta Sewak Samaj, Rohtak, Bharatya Jan Sangh, Punjab, Jullundur and Tenants of village Chachrari, District Ludhiana have also represented that daughters should inherit from the property of their fathers-in-laws|husbands and not from the property of their fathers and have suggested the amendment of the Hindu Succession Act, 1956 on the ground that the Act does not suit the agricultural and rural economy of the country

The Government do not propose to make any amendment in the law (the Hindu Succession Act, 1956) for this purpose, because in the first place, except the representations referred to above received from Punjab and Delhi no representation has been received from any other part or region of the country, from any organization or association In the second place, this shows that the people of the country to whom the Act applies have accepted the provisions of the Act. In the third place, the daughter's right was recognised by Parliament after very careful consideration of the matter for years. The Government do not think it proper to reverse this de-

cision after so many years: that will, in the opinion of the Government, be a retrograde step.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं विधि मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह राज्य सरकारों से इस संबंध में कुछ परामर्श लेने का विचार कर रहे है कि जब तक लड़की अविवाहित हो तब तक पिता की सम्पत्ति में उस का अधिकार हो लेकिन विवाहित होने के पश्चात् पति की सम्पत्ति में उस का अधिकार हो यानि विवाह के पश्चात् भी पिता की सम्पति में अधिकार न हो जिससे बहन और भाई के संबंधों मे परस्पर कटुता न हो, तो इस संबंध मे जैसे दिल्ली और पंजाब से आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास आये है इसी तरह से और राज्य सरकारों से भी वह परामर्श ले रहे हैं जिससे कि एक अखिल भारतीय नीति उत्तराधिकार के कानून के संबंध में निर्धारित कर सके ?

Shri D. R. Chavan: No, Sir.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आप ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू किया, जब भारत सरकार यह कहती है कि भारतवर्ष में सभी धर्म समान हैं तो यह कानून हिन्दुओं के ऊपर ही क्यों लागू किया जाता है, क्या सरकार का विचार इस कानन को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करने का है ?

Shri D. R. Chavan: The matter is under consideration to have a common code for all the communities. But there are certain difficulties coming in the way, and, therefore, it has not been possible to have it.

Further, the question why it has not been made applicable to other communities does not arise out of the main question.

श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इस कानून के बनने के बाद प्रान्तीय और केन्द्रीय, न्यायालयों में इस संबंध में कितने विवाद दायर किये गए और उन का क्या परिणाम रहा ?

Shri D. R. Chavan: That information has not been collected, nor is it available.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमन् मंत्री महोदय ने फरमाया है कि मालूम पड़ता है कि जनता ने इस उत्तराधिकार कानून को गृहीत कर लिया है परन्तु मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का यह दावा तथ्यों से बिल्कुल दूर है। क्या इस के लिए वह कोई जांच कमीशन बिठायेंगे जिससे पता चले कि कितने ऐसे ट्रांजैक्शनस हुए हैं और कितना उत्तराधिकार लडकियों को अब तक मिला है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि शायद ही सौ में से कहीं एक कोई केस ऐसा हो कि जिस में लड़की को उत्तराधिकार मिला हो । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता ने इस को गहित नहीं किया है और यह बिलकुल निरर्थक कानून है ।

Mr. Speaker: He has only made some statement; he has not put any question.

श्री बलराज मधोक : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इस कानून के संबंध मे उन्हे आवेदन केवल पंजाब और दिल्ली से प्राप्त हुआ है। तो क्या उन्होंने इस संबंध मे किन्हीं अन्य प्रान्तों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि उन प्रान्तों के अन्दर भी स्थिति इस प्रकार की है ? अगर वहां की जनता इतनी वोकल नहीं है और उन्होने आवाज नहीं उठायी तो क्या इस का मतलब यह लिया जाय कि वहां इसका विरोध नहीं है ? क्या यह वास्तविकता नही है कि इस कानून के कारण जो भारत का पारिवारिक सिस्टम है वह छिन्न-भिन्न हो रहा है और बहन भाई का जो पवित्र सम्बध था उस के अन्दर बहुत गिरावट आ गई है.....

Mr. Speaker: He is expressing his opinion. But this is the Question Hour.

श्री बलराज मधोक : और मंत्रि इस सुझाव को मान लिया जाय कि विवाह के बाद स्त्री को अपने श्वसुर के धन में से हिस्सा मिले तो उससे जो कानून का मूल मुद्दा था कि स्त्री को उस की सम्पत्ति मे भाग मिले वह मुद्दा पूरा हो जायगा और इससे यह जो सामाजिक जीवन पर संकट आयेगा वह भी दूर हो जायगा ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): The hon Member is only arguing the case and not putting any question

श्री बलराज मधोक : क्या इस संबंध मे मंत्री महोदय कुछ विचार करेंगे और क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

Shri D. R. Chavan: No, Sir

Shrimati Lakshmikanthamma: Following the same line of argument, why should the son not get the right to the property of his father-in-law? I would like to know from the hon Minister whether there has been a lot of intriguing and because the women are still uneducated and ignorant the brothers exploit them and do not give equal share of property to their sisters, and if so, what steps Government propose to take to see that justice is done to the women and whether any committee is going to be set up for this purpose?

श्री राम सेवक यादव अध्यक्ष महोदय, संविधान की इस व्यवस्था के रहते कि सभी सम्प्रदायो के लिए समान सिविल कानून होगा 20 वर्ष से अधिक हो चुका है मैं जानना चाहता हू कि इस दिशा मे सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये उसका क्या क्या परिणाम निकला है और अगर कदम नही उठाये तो रास्ते में कौन सी चीजे ऐसी हैं कि जो बाधक है उस पर क्या मंत्री महोदय रोशनी डालेंगे ?

Shri D. R. Chavan: So far as a common code applicable to all the communities is concerned, a number of steps have been taken But there are certain difficulties, as I have just now said .

Shri Bal Raj Madhok: We want to know what those difficulties are?

Shri D. R. Chavan: He may table a separate question on that, because that does not arise out of the main question

Shri Bal Raj Madhok: He says that there are certain difficulties He must tell us what those difficulties are

Shri D. R. Chavan: There are a number of difficulties which are coming in the way Opposition is coming

Shri J. B. Kripalani: Why should he not be frank and say that some communities stand against such a thing?

Shri D. R. Chavan: The difficulties are that certain communities to whom the common code has to be made applicable

Shri Bal Raj Madhok: They are not doing it because they want to have the Muslim votes

Shri Kanwar Lal Gupta. Is this their secularism?

Shri Bal Raj Madhok That is their secularism?

Shri D. R. Chavan: I may be allowed to complete my reply

For a common code, the initiative has got to come from the community concerned After all, it is a democracy and we cannot force upon omebody what you and I like

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरा तो प्रश्न था कि क्या कदम उठाए गए हैं ? 20 वर्ष संविधान लागू हुए हो गया। सभी सम्प्रदायों के लिए समान कानून बनाने के लिए क्या काम किया गया, यह मैं जानना चाहता हू, उस को तो बताया ही नहीं।

Mr. Speaker: He has already replied to the question.

Shri D. R. Chavan: I have already replied to the question.

श्री राम सेवक यादव : क्या प्रयास हुआ इतना ही बता दे ।

Shri J. B. Kripalani: The system of polygamy was bad for the Hindus Are not the Muslim ladies also our sisters? Would they also not like to have monogamy? Why not leave this question not to Muslim men but to Muslim women to decide?

Mr. Speaker: Is it a suggestion for action

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): That is a good suggestion.

Shri J. B. Kripalani: Why do they not leave it to the Muslim women?

Mr. Speaker: It is a suggestion for action

Shri J. B Kripalani: Why should they not take the opinion of the Muslim ladies? After all, polygamy is a handicap to our sisters It is not a handicap to the man, it is a handicap to the woman

An hon. Member: According to him

Shri J. B Kripalani: Unless a man has an educated wife, he cannot afford to have a few more wives Why do Government not take any steps to ascertain the opinion of the Muslim ladies in this respect?

Shri Govinda Menon: That is a good suggestion to be kept in mind

श्री राम सेवक यादव श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नही आया ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : जब से यह लडकियो को उन के पिताओ की जायदाद मे हिस्सा देने वाला कानून बना है तब से लेकर आज तक क्या उन्होने जमीनो के बारे में जाच की है कि हमारी जमीने थोडी-थोडी हैं और इस कानून से खाद्य समस्या पर बुरा असर पडा है क्योंकि जमीनो के और भी टुकडे हो गये हैं . . .

Mr. Speaker: He is arguing the case. There is no question.

श्रीमती जयाबेन शाह : क्या विधि मंत्री यह बतलायेंगे कि यह इजिप्ट, पाकिस्तान, आदि मिडिल ईस्ट मे मुसलमान औरतो को जितना हक दिया गया है उतना हक देने के बारे म वह क्या कदम उठाना चाहते हे ?

Shri Govinda Menon: As regards the enactment of a common code regarding succession, marriage etc for all the communities in India as contemplated in the Constitution, some steps and inquiries were made one or two years ago and the matter has not been closed Opinion was sought to be taken from the communities who will be affected, the opinion invariably even from members of Parliament belonging to the concerned communities was against the introduction of a common code for all the communities in India

Shri J. B. Kripalani: Are Muslim women a community or not?

Shri Govinda Menon: Acharya Kripalani suggested that so far as polygamy is concerned, it is the opinion of the women that should be taken

Shri Hem Barua: Why this partiality?

Mr. Speaker: That is Acharya Kripalani's suggestion, not the Law Minister's

Shri Govinda Menon. No such attempt has been made to ascertain the opinion of the ladies only

Shri J B. Kripalani: Will he make an attempt?

Shri Govinda Menon: Regard being had to the interest the House is showing in the matter, further attempts will be made

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: On a point or order. मेरी व्यवस्था आप से यह है कि आप मंत्रियों को

कमसे कम इस प्रकार का निर्देश अवश्य दें कि प्रश्न जिस भाषा में किया जाये उस का उत्तर भी उसी भाषा में आये। आप ने शायद अच्छे तरीके से सुना होगा कि श्रीमती जयाबेन शाह का एक सीधा प्रश्न यह था कि इजिप्ट, पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं को जितनी सुविधा प्राप्त है उतनी सुविधा क्या भारत वर्ष में भी मिलेगी ? इस का उत्तर आना चाहिए था लेकिन मंत्री महोदय ने उस का उत्तर न देकर दूसरी ओर चले गये। मैं आप से व्यवस्था चाहता हू कि इस सम्बन्ध मे कब से मंत्रियो को निर्देश मिलने वाला है?

Mr. Speaker: That is a good idea What Pakistan and Egypt has done, are we prepared to do?

Shri Govinda Menon: That will be considered

Allotment of Foodgrains to States following the West Asian Crisis

\+

*1057 **Shri P. C. Adichan:**
Shri Vasudevan Nair:
Shri C. Janardhanan.
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri R. Barua:
Shri D. N. Patodia:
Shri S. Kundu:
Shri J. Ahmed:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Baidhar Behera:
Shri Samar Guha:
Shri Ram Charan:
Shri M. C. Majhi:
Shri Sradhakar Supakar:
Shri M. L. Sondhi:
Shri Rabi Ray:
Shri Kameshwar Singh:
Shri D. C. Sharma:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri Nihal Singh:
Shri D. N. Deb:
Shri Sheopujan Shastri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have consulted the State Governments and come to a final decision about the allotment of foodgrains to States following the West Asian crisis; and

(b) if so, the allotments for the various States?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Chief Ministers of the States were duly apprised that due to the closure of the Suez Canal, arrivals of foodgrains will be considerably delayed and supplies will be smaller There was no time to formally consult all the State Governments before deciding the quantities that could be supplied to the various States during the month.

(b) The allotments that were originally made and the revisions that became necessary after the closure of the Suez Canal during the month of June are indicated in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No* Lt-976/67]

श्री अदिचन क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केरल वासियो के लिए दूसरे प्रान्तो मे कितना चावल जून और जुलाई के महीने मे भेजा गया ?

Shri Kanwar Lal Gupta: He should reply to the question in Hindi

Mr. Speaker: I cannot compel any Member It is the choice of the individual Member.

Shri Kanwar Lal Gupta: It is a request through you to him

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केरल में 62,000 टन चावल भेजा गया।

Shri R. Barua: Assam's quota of wheat was reduced from 30,000 tonnes per month to 5,000 tonnes per month. Out of that also, in May and june the full quota was not gives What is the position at the present moment?

Shri Annasahib Shinde: Now, we have allotted 15,000 tonnes to Assam. Of course, there are floods and other